प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

20.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / रितेश कपूर / 15.00 बजे

जीएसटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में, देश में कर–व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो। नई दरें आगामी सोमवार से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में, हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र पर जी.एस.टी. सुधार के संभावित प्रभावों पर एक नजर डालते हैं।

सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी की दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी रहती है एयर कंडीशनर और डिशवॉशर जैसी वस्तुओं पर कर की दर को 28ः से घटकर 18ः कर दिया गया है वहीं टेलीविजन और गैर टीवी मॉनिटर पर भी जीएसटी दर को घटकर 18ः कर दिया गया है जो पहले 28ः के तक्षशिला में आती थी कटौती से बाजार में इन उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली की शुभान मिश्रा ने इन सुधारो का स्वागत किया है। एसी और टीवी पर जो जीएसटी रेट कम हुआ है, यह सरकार द्वारा किया गया सराहनीय निर्णय है। यह बदलाव विशेष रूप से मिडिल क्लास लोगों के काफी राहतकारी है। इस टैक्स कटौती से एसी और टीवी की कीमत इतनी कम हो जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ घटेगा। यह निर्णय जनहित के लिए एक सकारात्मक कदम है।त्योहारों के सीजन सै पहले इन सुधारों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की मांग बनने की उम्मीद है, नए का सुधार इस सोमवार से लागू होंगे।

राजेश धर्माणी

प्रदेश सरकार राज्य में हर साल बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निर्माण कार्यों के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश वासियों को अब पंचायत क्षेत्र में घर बनाने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द ही नये नियम लागू करने जा रही है। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल आपदा संभावित क्षेत्र है ऐसे में लोगों की संपत्ति और जान बचाना जरूरी है। इससे सुनियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

राजेश धर्माणी ने जीएसटी सुधारों का भी समर्थन किया और कहा कि इससे आम लोगों को फायदा होगा।

कामगार

भवन निर्माण व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा है कि बोर्ड का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने इसकी कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। नरदेव सिंह कंवर ने आज शिमला में कहा कि बोर्ड की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित की जा रही है ताकि प्रदेश के पात्र कामगारों को फायदा पहुंचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने कामगारों की ई–केवाईसी और भौतिक सत्यापन आरंभ किया है ताकि पात्र लोग ही पंजीकृत होंगे। इससे बोर्ड की योजनाओं का दुरूपयोग रूकेगा और पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा।

<u>बस सेवा</u>

चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने कहा है कि घाटी के सुराल से शिमला चलने वाली राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा बंद हो जाने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और पांगी प्रशासन से आग्रह किया है कि इस बस सेवा को तुरंत बहाल किया जाए ताकि पांगी घाटी की जनता को छोटी गाड़ियों के भारी भरकम किराए से राहत मिल सके।

<u>सामाजिक सुरक्षा पैंशन</u>

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन ले रहे लोगों से 30 सितम्बर तक ई–केवाईसी और सत्यापन करवाने का आग्रह किया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि यदि ये सत्यापन नहीं करवाया गया तो संबंधित लोगों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन रूक सकती है। प्रवक्ता ने प्रात्र लोगों से आंगनबाड़ी वर्करों के माध्यम से ई–कल्याण ऐप पर ई–केवाईसी और सत्यापन करवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए इन दिनों प्रदेश में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

<u>मौसम</u>

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अभी तक सामान्य से 46 फीसदी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष मॉनसून के दौरान अभी तक एक हज़ार 21 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो–तीन दिनों में प्रदेश के कुछ भागों से मॉनसून के वापस जाने के लिए

परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। विभाग ने 21 से 23 सितम्बर तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है।